No bank specific Recovery Tribunals have been set up.

(b) Does not arise.

Criminal Prosecution against Government Officers in Share-Scam case

6426. SHRI RAMNATH KOVIND: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government of India are aware of the criminal prosecution by Orissa Government against its officers involved in share-scam;

(b) whether the Central Government also initiated similar action against their defaulting officers in this regard;

(c) if so, the details of action taken against such officers and the nature of action taken, class-wise; and

(d) whether there are any cases of exemption from criminal prosecution and if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Enquiry against Former Member of Planning Commission

6427. SHRI GURDAS DAS GUPTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a former member of Planning Commission was involved in a number of financial irregularities including foreign funds;

(b) if so, whether the CBI has started enquiry in foreign countries also with regard to these complaints; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) Central Bureau of Investigation has reported that four cases were registered against Shri V. Krishnamurthy, Ex-Member, Planning Commission & others on the allegations of various financial irregularities. Out of these cases, chargesheets have been filed in two cases. CBI has also started enquiries in foreign countries in connection with complaints against Shri Krishnamurthy.

According to C.B.I., these cases relate to allegations of abuse of official position in getting certain banks and undertakings to extend loans and favours to the firms owned by his sons and relatives in India and abroad and on receipt of illegal gratification.

ग्रामीण विकास निधि से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी गयी सहायता

6428. **श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरौला:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने स्वैच्छिक संगठनों को ग्रामीण विकास निधि से कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की सहायता दिये जाने के लिए प्रक्रिया क्या है; और

(ग) इन संगठनों के क्रियाकलाप क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने अपनी तकनीकी सहायता निधि (टी ए एफ) से स्वैच्छिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की है न कि ग्रामीण विकास निधि (आर डी एफ) से।

(ख) और (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि स्वैच्छिक एजेंसियों को निधि की मंजूरी और उसे जारी करना उनसे प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित होता है। ऐसी स्वैच्छिक एजेंसियां जो औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी/स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान कर दलितों के आर्थिक उन्नयन में लगी है, सहायता की पात्र हैं। पात्रता के लिए, स्वैच्छिक संस्थानों को रजिस्टर संगठन होना चाहिए तथा उनके द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के लिए उन्हें पूंजी व्यय और आवर्ती व्यय के एक अंश की व्यवस्था करनी चाहिए। 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 142

स्वैच्छिक संस्थाओं को 13.20 करोड़ रुपए की कुल सहायता प्रदान की।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका संबंधी दिशानिर्देश

6429. **श्री कनक सिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका के संबंध में सरकार द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कौन-कौन से दिशानिर्देश जारी किए हैं और ये दिशानिर्देश कब जारी किये गये थे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना उद्योग का वित्तपोषण, संवर्धन या विकास करने के कार्य में लगी संस्थाओं के कार्यकरण का समन्वय करने, उद्योग के विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन संस्थाओं के विकास में सहायता करने और इनसे संबंधित मामलों के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप एक प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत जुलाई 1964 में की गई थी। जबकि सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका के संबंध में कोई विशिष्ट मार्गनिर्देश जारी नहीं किए गए, लेकिन कुछ अवसरों पर सरकार ने विशिष्ट विषयों पर मार्गनिर्देश जारी किए गये हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और लघु उद्योग विकास बैंक की सफलता की दर

6430. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक / लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता की दर बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इन बैंकों द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता की दर का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि वह अपनी गतिविधियों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में सक्षम रहा है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूर की गई सहायता 1991-92 में 7590 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 1992-93 में 9459 करोड़ रुपए और 1993-94 में 12.944 करोड़ रुपए (अनंतिम) हो गई है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा मंजूर की गई सहायता 1990-91 में 3407 करोड़ रुपए से बढ़कर 1992-93 मे 3550 करोड़ रुपए और 1993-94 में और बढ़कर 4014 करोड़ रुपए हो गई है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने अपने परिचालनों के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करने और लघु उद्योग क्षेत्र में निवेश करने में पर्याप्त योगदान किया है।

Opening of Regional Rural Banks in Gujarat

6431. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number and locations of branches of Regional Rural Banks opened during the year 1992-93 and 1993-94 so far in the country particularly in the State of Gujarat, State-wise;

(b) whether Government propose to open more number of branches of Regional Rural Banks in the country and in Gujarat State during the next financial year; and

(c) if so, the details thereof and the locations of such banks?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) Reserve Bank of India (RBI) has reported that as a matter of policy, pending decision regarding restructuring of the Regional Rural Bank (RRBs) no centres were allotted for opening of branches to RRBs under the Branch Expansion policy of 1990-95 which includes the current financial year. However, as reported by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), 4 branches